Inclusive Development: Importance of Inclusive Development in India

समावेशी विकास : भारत में समावेशी विकास का महत्व

Kushal Kumar Bhoi

कुशल कुमार भोई

सहायक आचार्य अर्थशास्त्र राज नोबल्स डिग्री कॉलेज डूंगरपुर (राज .)

समावेशी विकास से आशय समावेशी विकास से तात्पर्य आर्थिक विकास से सभी वर्गों को लाभ मिले और गरीबी कम हो , समावेशी विकास का अर्थ है सभी तक बाजार संसाधनों तक पहुंचने का समान अवसर देना और सभी के लिए उचित वातावरण उपलब्ध कराना है समावेशी विकास के अंतर्गत शिक्षा और कौशल के लिए लोगो को सशक्त करना शामिल है अर्थात अवसरों की समानता के साथ विकास को बढ़ावा देना है

समावेशी विकास में सकल घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि परिलक्षित होती है जिससे आय की असमानता दूर होती है समावेशी विकास में जनसंख्या के सभी वर्गो के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है अर्थात आवास, वस्त्र , , भोजन , पेयजल , शिक्षा , स्वास्थ्य के साथ एक गरिमापूर्ण जीवन यापन के लिए रोजगार के साधन उत्पन्न करना है समावेशी विकास में पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाना अतिआवश्यक है क्योंकि पर्यावरण की कीमत पर किया गया आर्थिक विकास उचित नहीं कहा जा सकता है।

भारत में समावेशी विकास भारत में समावेशी विकास की अवधारणा सबसे पहले 11 वी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत की गई। इस योजना में समाज के सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई।

12 वी पंचवर्षीय योजना भी समावेशी विकास पर आधारित थी जो तीव्र , समावेशी , और सतत विकास के उद्देश्य पर आधारित थी इस योजना में गरीबी , शिक्षा ,स्वास्थ्य और आजीविका के अवसर प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया।

भारत सरकार द्वारा समावेशी विकास के अंर्तगत ही वित्तीय समावेशन के द्वारा कई उपाय किए गए है इनमे मोबाइल बैंकिंग , प्रधानमंत्री जन धन योजना , प्रधानमंत्री मुद्रा योजना , पेंशन और बीमा इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है।

समावेशी विकास की आवश्यकता

समावेशी विकास के अभाव में कोई देश अपना विकास नही कर सकता है क्योंकि समावेशी विकास आर्थिक विकास के साथ साथ यह सामाजिक और नैतिक विकास भी है। समावेशी विकास की आवश्यकता निम्न तरह से स्पष्ट होती है

समावेशी विकास , सुस्थिर विकास के लिए आवश्यक है बिना समावेशी विकास के सुस्थिर विकास संभव नहीं है उसमे गिरावट आ जायेगी।

समावेशी विकास के अभाव में आय वितरण में असमानता आ जायेगी जिससे धन का सकेंद्रण बढ़ेगा अतः आय के समान वितरण के लिए समावेशी विकास आवश्यक है।

समावेशी विकास के अभाव के कारण देश में असंतोष , साम्प्रदायिक तनाव और क्षेत्रवाद की घटनाएं उत्पन्न होती है अतः ऐसी विकट परिस्थितियों से दूर रहने के लिए समावेशी विकास आवश्यक है।

समावेशी विकास की बाधाएं

निर्धनता और बेरोजगारी भारत में व्यापक रूप में निर्धनता और बेरोजगारी है जो समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक है।

स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण लोग इन सुविधाओं से वंचित है।

आर्थिक चुनौतियां आर्थिक चुनौतियां जैसे कृषि भू जोत का विखंडन , संस्थागत ऋण का अभाव , वित्तीय जानकारी का अभाव , निम्न विकास दर इत्यादि।

पर्यावरण प्रदूषण जल , वायु और ध्वनि प्रदूषण समाज को प्रभावित करता है।

उच्च स्तरीकृत समाज भारतीय समाज धर्म , जाति और भाषागत दृष्टि से अलग अलग वर्गो में बटा हुआ है जिसके कारण समावेशी विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

क्षेत्रीय असंतुलन क्षेत्रीय असंतुलन भारत में एक महत्वपूर्ण समस्या है क्षेत्रीय असंतुलन के कारण निर्धनता और धन का असमान वितरण समाज में बढ़ता है।

समावेशी विकास में बाधाओं के निराकरण के उपाय

कृषि क्षेत्र का विकास कृषि क्षेत्र का अधिकाधिक और उपयुक्त विकास किया जाना चाहिए ताकि रोजगार में वृद्धि हो और निर्धनता और बेरोजगारी में कमी आए।

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्योगों का विकास एमएसएमई श्रम गहन क्षेत्र है अतः इसका अधिकाधिक विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इन्हे पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए ताकि इनका समुचित विकास होने पर इनमे रोजगार की मात्रा बढ़े। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और निर्धनता में कमी होगी।

पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता विकसित राज्यों की तुलना में पिछड़े राज्यों को अधिकाधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए ताकि इन राज्यों के विकास को गति मिल सके और वहा रोजगार की मात्रा में वृद्धि हो सके। और निर्धनता दूर हो सके जिससे वहा आय की असमानता दूर हो सके।

आधारभूत क्षेत्र का विकास आर्थिक और सामाजिक आधारभूत सेवाएं पर्याप्त मात्रा में विकसित की जानी चाहिए। इन क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाना चाहिए। ताकि उधोग धंधे आसानी से विकसित हो सके और व्यापार का विकास और वृद्धि हो सके जिससे रोजगार बढ़ाया जा सके।

आय का समान वितरण संसाधनों और आय का समान वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकार को अपनी नीति इस तरह निर्मित करनी चाहीए की धन का सकेंद्रण नही हो सके धन का समान वितरण निर्धनता को दूर करने का महत्पूर्ण उपाय है।

जनजातीय और ग्रामीण समुदाय जनजातीय और ग्रामीण समुदाय को शिक्षित करना , साफ पानी , खाद्य सुविधाओं , बिजली की उपलब्धता , पक्के घर और उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि के उपाय किए जाने चाहिए।

महिला सशक्तिकरण शिक्षा , कौशल, प्रशिक्षण और उधमिता कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं , कानूनी सेवाओं और रोजगार के अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

जागरूकता कार्यक्रम समावेशी विकास और समान अवसरों के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। रूढ़िवादिता , पूर्वाग्रह और भेदभाव को मिटाने के लिए अभियान , कार्यशालाएं और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

समावेशी विकास को प्राप्त करने लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

ग्रामीण विकास विभाग आजादी के अमृत महोत्सव के तहत समावेशी विकास के लिए अग्रणी विभाग है राष्ट्रीय कार्यान्वन समिति ने समावेशी विकास विषय के तहत 9 अभियानों को मंजूरी दी है जो निम्न है

1 समग्र आवास पीएमएवाई जी के तहत अभिसरण

2 जिला स्तर पर वित्तीय साक्षरता

3 ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना

4 स्वस्थ्य महिला समृद्ध आगाज

5 स्व सहायता समूह महिलाओं द्वारा प्राकृतिक खेती

6 आकांक्षी जिलों में पशुधन जागृति अभियान गहन जागरूकता अभियान

7 स्वामित्व , मेरी संपति , मेरा हक

8 एसएचजी नेटवर्क में पात्र ग्रामीण महिलाओं को शामिल करना

9 नदी तटों पर वृक्षारोपण अभियान

उक्त सभी योजनाओं से निश्चित रूप से समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा जिससे लोगो के जीवन स्तर में आवश्यक सुधार दृष्टिगोचर होगा।

भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर गरीबी उन्मूलन , सतत विकास और समावेशी विकास को निरंतर जारी रखना चाहिए ताकि सभी वर्गो का उचित विकास संभव हो सके। सरकारों को स्वयंसेवी संगठनों और निजी क्षेत्र के सहयोग और उचित भागीदारी के द्वारा समावेशी विकास के के लक्ष्य को पूरा किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

योजना आयोग 11 वी पंचवर्षीय योजना।

योजना आयोग 12 वी पंचवर्षीय योजना।

https://akam samaveshivikaas.nic.in